



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

16
22/5/2002

सं. 204]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2001/श्रावण 8, 1923

No. 204]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2001/SRAVANA 8, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2001

विषय: भारत में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित थर्मल सेंसिटिव कागज के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करना।

सं. 30/1/2001-झीजीएडी.—मैसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिकादायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसिटिव पेपर के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

.2. विचाराधीन उत्पाद: वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद थर्मल सेंसिटिव पेपर (जिसे इसके पश्चात् संबद्ध वरतु कहा गया है)। थर्मल सेंसिटिव पेपर एक ऐसा पेपर है, जिस पर रसायनों का एक विशेष लेप चढ़ा होता है ताकि बेस पेपर को थर्मल सेंसिटिव गुणधर्म प्रदान किए जा सके। पेपर पर यह प्रभाव उक्त पेपर पर नियमित थर्मल ऊष्मा देकर पैदा किया जाता है। थर्मल सेंसिटिव पेपर का उपयोग मुख्यतः इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के लिए संदेश रिकार्ड करने हेतु किया जाता है जहां मशीन का प्रयोग ऊष्मा किरणों की संवेदनशीलता के जरिए संदेश रिपोर्ट रिकार्ड करने में

किया जाता है। थर्मल सेंसिटिव पेपर का उपयोग मुख्यतः फैम्स मशीनों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ईसीजी मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरणों, सेस्मोग्राफिक मशीनों, एयर लाइन्स बैगेज टैंगिंग, टिकटों, बोर्डिंग कार्डों इत्यादि में भी किया जाता है। याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि टी एस पी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इस उत्पाद का कोई अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। तथापि, आमतौर पर यह उपशीर्ष 4809.10 अर्थात् कार्बन अथवा इसी प्रकार का कॉर्पिंग पेपर में शामिल है। याचिकाकर्त्ताओं ने यह भी दावा किया है कि टी एस पी की स्वीकृति सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के शीर्ष 4811 और 4816 के विभिन्न उप शीर्षों में भी दी जाती है। ये वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और ये वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं।

घरेलू उद्योग

3. यह याचिका मैसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है और इसलिए वह उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य हैं (जिसे इसके बाद संबद्ध देश अथवा चीन जनवादी गणराज्य कहा गया है)

समान वस्तु

5. याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, चीन जनवादी गणराज्य के मूल के या वहा से निर्यातित माल के समान वस्तु है। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन से याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित माल के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

6. सीमा शुल्क टैरिफ (पाइत वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 की परिशिष्ट 1 में दिनांक 15.7.99 की अधिसूचना सं.44/99-सी यू एस (एन टी) द्वारा संशोधन कर उसमें निम्नलिखित सिद्धांत 7 शामिल किया गया था:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत अथवा परिकलित लागत के आधार पर अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां यह संभव न हो वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजन करके समान वस्तु हेतु भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबद्ध देश के विकास स्तर और संदर्भधीन उत्पाद (31 मई 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.28/2001 द्वारा शामिल) को ध्यान में रखते हुए, उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसीय सूचना का विधिवत् ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो वहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में यदि कोई जांच की गई है तो उसकी समय-सीमा का ध्यान भी रखा जाएगा । जांच संबंधी पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन की सूचना अविलम्ब दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय सीमा प्रदान की जाएगी ।

इन नियमों में दिनांक 31.5.2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं.28/2001(एन टी)द्वारा आगे और संशोधन किया गया है जिसके द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत 8 सम्मिलित किया गया है और इसकी टिप्पणी में चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है ।

इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढॉचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे कि ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य पता चल सके । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या:-

- (i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागतों और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, निविष्टि, बिक्रियां एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय बाजारी संकेतों जो

आपूर्ति एवं मांग प्रदर्शित करते हैं, के अनुरूप और इस बारे में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिया जाता हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य प्रर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं;

- (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली खासकर पारिसंम्पत्तियों के मूल्य हास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनियम व्यापार और शृणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं;
- (iii) ऐसी फर्में दिवालिएपन और सम्पत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्म के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं; और
- (iv) विनियम दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है;

किन्तु रूस और चीन जनवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को बेखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट कारकों के बारे में लिखित में, पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 तक में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है

टिप्पणी:

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल हैं अल्बानिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चीन जनवादी गणराज्य, जार्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सिर्जिस्तान, मंगोलिया, रूस, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उज़बेकिस्तान एवं तिएतनान। इनमें से ऐसा कोई देश जो यह प्रमाणित करना चाहता है कि वह इस पैराग्राफ में वर्णित मापदंड के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरा ध्यान किया जाएगा।

उपरोक्त यथासंशोधित नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने सामान्य, प्रशासनिक और बिक्री लागत एवं लाभों हेतु उचित अभिवृद्धि के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

उपरोक्त नियमों के अनुसार, यदि संबद्ध देश के निर्यातक अपने निर्यातों को बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में किए जाने का दावा करते हैं तो उनके लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

निर्यात कीमतः

याचिकाकर्त्ताओं ने आंकड़ों के गौण स्रोतों के आधार पर संबद्ध देश की निर्यात कीमत का दावा किया है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क(1) (ख)के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने निर्यात कीमत का परिकलन भी उस कीमत के आधार पर किया है जिस कीमत पर आयातित वस्तुएं सर्वप्रथम किसी स्वतंत्र क्रेता की पुनःबेची जाती हैं । कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, चीन जनवादी गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा बदरगाह पर हैण्डलिंग तथा पैकिंग प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है ।

पाटन मार्जिन

8. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य, जिसका दावा सामान्य, प्रशासनिक और बिक्री लागत एवं लाभों हेतु उचित अभिवृद्धि के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया गया है, निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिससे इस बात का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति

9. क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे बिक्री प्राप्ति में गिरावट, कीमत में कटौती, कम क्षमता उपयोग, वस्तुसूचियों में वृद्धि, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत न मिलने से घरेलू उद्योग को नुकसान, समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

पाटनरोधी जांच का आरंभ

10. उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की, या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 तक की है।

सूचना देना

12. इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत सरकार, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क निदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं। अन्य कोई हितबन्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

समय सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एस. बी. सप्तश्रृंग, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2001

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Thermal Sensitive Paper from Peoples' Republic of China into India.

No. 30/1/2001-DGAD.— M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, New Delhi have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Thermal Sensitive Paper originating in or exported from People's Republic of China and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product involved in the present petition is Thermal Sensitive Paper (TSP) (hereinafter referred as subject goods). Thermal Sensitive Paper is a paper coated with a special mix of chemicals for providing thermal sensitive properties to the base

paper. Impression on the paper is created by virtue of controlled thermal heat exposed on the paper. Thermal Sensitive Paper is primarily used for recording messages for electronic equipments where the machine is used to record messages, reports through sensitivity of heat rays. Thermal Sensitive Paper is primarily used in fax machines. It is also used in ECG Machines and other medical equipments, Seismographic machines, Airlines baggage tagging, tickets, boarding cards etc. Petitioners have claimed that TSP is classified under chapter 48 of the Customs Tariff Act. The product does not have a dedicated Customs Classification. However, it generally gets covered under sub-heading 4809.10 i.e. 'Carbon or similar copying paper'. Petitioners have also claimed that TSP is also cleared under different sub-headings of heading 4811 and 4816 of the Customs Tariff Classification. These Classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, New Delhi. The petitioner has claimed that it is the only producer of the subject goods in India and therefore, satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3)(a) of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

4. The country involved in the present investigation is the Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as the subject country or China PR).

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from China PR. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' to that imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

NORMAL VALUE

6. Annexure 1 to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 had been amended vide Notification No. 44/99-CUS(NT), dated 15-7-99 whereby the following Principle 7 had been inserted:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner *keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question* (inserted vide Custom Notification No. 28/2001 dated 31st May 2001), and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

These Rules have been further amended vide Custom Notification No. 28/2001(NT) dated 31-5-2001 whereby Principle 8 as under has been inserted and in the Note appended thereto Peoples' Republic of China has been included in the list of non-market economy countries:

"The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in that note and includes any country which the designated authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the designated authority shall consider as to whether,

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;**

235961/201-3

- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

Note: For the purposes of this paragraph, the list of non-market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakhstan, North Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the designated authority".

In accordance with the Rules as amended above, the petitioners have claimed Normal Value on the basis of constructed cost of production of the subject goods in India with reasonable addition for general, administrative and selling cost and for profits.

In terms of the aforesaid Rules it will be incumbent upon the exporters from the subject country, in case they claim their exports to be from market economy conditions, to provide sufficient evidence to the Designated Authority in accordance with the aforesaid Rules.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have claimed export price from the subject country based on the secondary data sources. The petitioners have also constructed the export price on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent

buyer, in accordance with Section 9A(1)(b) of the Customs Tariff Act. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, commission, inland transportation in China PR, port handling and packing charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

8. DUMPING MARGIN

The Normal Value of the subject goods in the subject country, which is claimed on the basis of constructed cost of production of the subject goods in India with reasonable addition for general, administrative and selling cost and for profits, is significantly higher than the net export price indicating *prima-facie* that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Various parameters relating to injury such as the decline in the sales realization, price suppression, sub-optimal utilization of capacity, increase in inventory and losses to the Domestic Industry due to non-realization of fair and reasonable price from sale of the subject goods, *prima-facie* indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2000 to 31st December 2000.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request whatsoever shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority